www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

सत्यमेव जयते

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 350

रोज़गार समाचार

सामाहिक

खण्ड 38 अंक 37 पृष्ठ 56 | नई दिल्ली 14 - 20 दिसंबर 2013 | ₹ 8.00

विद्युत की उपलब्धता

श्रीधर कुंडू

भारत ने पिछले कुछ दशकों में एक विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पर विद्युत की उपलब्धता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है. भारत की कुल स्थापित क्षमता 31 अक्तूबर 2013 के अनुसार 2,29,251 मे.वा. (मेगावाट) है. कुल क्षमता में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा 39 प्रतिशत है, जबकि निजी क्षेत्र और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 32 प्रतिशत और 29 प्रतिशत है. संयंत्रों से देश के विभिन्न हिस्सों में विद्युत पहुंचाने के लिए पारेषण लाइनों (66 केवी से ऊपर) की कुल लंबाई 1,02,540 सीकेएम (सर्किट किलोमीटर) है. घरों, फर्मों जैसे और अन्य अंतिम उपभोक्ताओं के स्तर पर उप-पारेषण स्तर में विद्युत आपूर्ति के लिए वितरण लाइनों (33 केवी और कम) का एक व्यापक नेटवर्क है.

विद्युत भारत के संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है जिस पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों का कार्याधिकार क्षेत्र है. व्यवहार में, इसका अर्थ है कि केंद्र विद्युत की उपलब्धता से संबंधित सभी अंतर-राज्य और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की देखरेख करता है, जबकि राज्य सरकार राज्य के आंतरिक मामलों के लिए ज़िम्मेदार है. राज्यों में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से जुड़े कार्यों के निवर्हन के लिए विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 में राज्य विद्युत बोर्डों की स्थापना का प्रावधान है. इस अधिनियम के तहत, विद्युत की उपलब्धता में तकनीकी समर्थन उपलब्ध करवाने के लिए 1951 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की एक वैधानिक संस्था के तौर पर स्थापना की गई थी. वर्ष 1947 में अखिल भारतीय कुल स्थापित क्षमता 1362 मेगावाट थी और इसका स्वामित्व ज़्यादातर राज्य सरकारों के पास था. केंद्रीय सरकार ने 1980 के दशक के शुरू में विद्युत (आपूर्ति) संशोधन अधिनियम, 1976 के साथ विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश किया और इसके बाद 1991 के बाद आर्थिक सुधारों के जरिए निजी क्षेत्र की इसमें प्रविष्टि हुई.

लेकिन 1990 के दशक तक विद्युत वितरण का प्रभार राज्य विद्युत बोर्डों के पास रहा. चूंकि वितरण कार्यों में बिजली की बिक्री से होने वाला नकदी प्रवाह शामिल होता है, इसके लिए अंतः उपयोगकर्ताओं से कार्यव्यवहार करने हेतु काफी दक्षता की ज़रूरत महसूस की गई. लेकिन यह तर्क दिया गया कि राज्य विद्युत बोर्ड इस क्षेत्र में असफल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप सीधे तौर पर इनके विघटन के लिए सुधार प्रक्रिया सामने आई. राज्य विद्युत बोर्डों की अधिक दक्षतापूर्ण कार्य करने के वास्ते उत्पादन, पारेषण और वितरण के कर्त्तव्यों के निवर्हन हेतु अलग-अलग संस्थाएं बना दी गईं. इन सुधारों की शृंखला में ओड़िशा सबसे पहला राज्य था और इसके बाद दिल्ली में ये सुधार लागू किये गये. वितरण के क्षेत्र में प्रचालन हेतु निजी क्षेत्र को अनुमति दे दी गई. विद्युत अधिनियम, 2003 ने सभी राज्यों में राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन को अनिवार्य कर दिया. इस अधिनियम में उपयुक्त टैरिफ दरों पर अंतिम उपयोगकर्ताओं को उत्पादन से की जाने वाली विद्युत आपूर्ति के कार्य की निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर विद्युत विनियामक आयोग बनाने का भी प्रावधान किया गया था. भारतीय विद्युत क्षेत्र में ये सभी सुधार सबको पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किये गये थे. दुनिया में भारत सबसे कम ऊर्जा उपभोगकर्ताओं का देश है. अक्तूबर 2013 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 917.18 केडब्ल्यूएच (1केडब्ल्यूएच= 1 यूनिट) है. लेकिन ये अधिकतर विकसित और विकासशील देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति बहुत कम खपत है. कनाडा की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 15145 और अमरीका की प्रति व्यक्ति खपत 13361 केडब्ल्यूएच है. चीन में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 2945 केडब्ल्यूएच है. यहां तक कि भारत में भी विभिन्न राज्यों में विद्युत खपत मात्रा में काफी विषमताएं हैं. कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम ऊर्जा खपत स्तर हैं. उदाहरण के लिए अक्तूबर 2013 को बिहार की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत केवल 133 केडब्ल्यूएच है, हालांकि गोवा की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 2025 केडब्ल्यूएच है.

ऊर्जा घाटा या विद्युत घाटा, जिसे विद्युत की आवश्यकता और इसकी उपलब्धता के बीच के अंतर के तौर पर परिभाषित किया जाता है, भारत में काफी ऊंचा है. वर्ष 2011-12 में, कुल विद्युत उत्पादन 876 अरब यूनिट था और विद्युत घाटा कुल आवश्यकता का 8.5 प्रतिशत था. देश में विद्युत घाटे का उच्च स्तर आर्थिक विकास के लिए नुक़सानदेह हो सकता था. भारतीय कृषि का यंत्रीकरण हो रहा है और इस क्षेत्र में वर्षों से बिजली का इस्तेमाल बढ़ा है. वर्ष 1947 में कृषि में उपभोग होने वाली विद्युत की मात्रा देश में कुल विद्युत खपत का मात्र 3 प्रतिशत थी, लेकिन वर्ष 2012-13 तक यह हिस्सा बढ़कर 18 प्रतिशत तक पहुंच चुका है. भारतीय उद्योग, विद्युत पर अत्यधिक निर्भर हैं. लेकिन कुल विद्युत खपत में अन्य क्षेत्रों के हिस्से में वृद्धि के साथ, इसमें उद्योग क्षेत्र का हिस्सा कम होता जा रहा है और वर्तमान में विद्युत खपत का औद्योगिक हिस्सा 45 प्रतिशत है.

खपत होने वाली कुल विद्युत में घरेलू विद्युत खपत का हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. वर्ष 1947 में, आवासों में विद्युत खपत का हिस्सा 10 प्रतिशत था और 2012-13 में यह 22 प्रतिशत तक हो गया. घरेलू विद्युत खपत में तीव्र वृद्धि के बावजूद देश में बहुत से घर अब भी बिजली की पहुंच से बाहर हैं. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किये गये आवास खपत व्यय सर्वेक्षण 2011-12 के अनुरूप 27 प्रतिशत ग्रामीण आवास और 4 प्रतिशत शहरी आवास रोशनी के लिये बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा विद्युत आपूर्ति से जुड़े घरों का एक बड़ा हिस्सा विद्युत की ख़राब गुणवत्ता की शिकायत करते रहे हैं. केंद्रीय सरकार ने प्रत्येक गांव में बिजली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरूआत की थी. लेकिन अभी तक देश में कुल गांवों में से 13 प्रतिशत का विद्युतीकरण नहीं किया गया है. आंचलिक, क्षेत्रीय और आवासीय स्तर पर कम विद्युत खपत के ये आंकड़े और विद्युत संपर्कता की कमी यह दर्शाती है कि देश में उच्चतर विद्युत खपत के लिए संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही यह विद्युत उपलब्धता में भी महत्वपूर्ण वृद्धि किये जाने के प्रति एक चेतावनी है. वर्तमान में देश विद्युत उत्पादन के स्रोत के तौर पर कोयला पर अत्यधिक निर्भर है. कुल उत्पादन में इसका 58 प्रतिशत हिस्सा बनता है. विद्युत उत्पादन के अन्य स्रोतों में जल विद्युत का हिस्सा 18 प्रतिशत और इसके बाद नवीकरणीय स्रोतों का हिस्सा 12 प्रतिशत होता है, जबकि 9 प्रतिशत गैस और 2 प्रतिशत हिस्सा परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत आता है. बढ़ती आवश्यकताओं का, विद्युत उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल पर अधिक दबाव पड़ेगा, जिसका पर्यावरण पर दुष्प्रभाव हो सकता है. अतः देश के विद्युत क्षेत्र के विविधीकरण और कुल विद्युत उत्पादन में जलविद्युत, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाये जाने की आवश्यकता है. दूसरे, विद्युत उत्पादन के स्रोतों को लागत प्रभावी किये जाने की आवश्यकता है. वर्तमान में विद्युत की औसत लागत रु. 3.50 है. सभी बीपीएल आवासों को मुफ्त विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ 1980 में शुरू की गई ''कुटीर ज्योति योजना'' को पुनर्जीवित करने के लिए विद्युत का उत्पादन, लागत प्रभावी अवश्य होना चाहिए. इसके लिए ग़ैर-परंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन में नई प्रौद्योगिकी लाने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होगा, जिसके लिये केंद्रीय सरकार और राज्यों से दृढ़ नीतिगत प्रयासों के साथ-साथ निजी क्षेत्र से उपयुक्त योगदान की आवश्यकता होगी.

(लेखकः सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबलिटी (सीबीजीए), नई दिल्ली से जुड़े हैं, ई-मेलः sridhar@cbgaindia.org)

महत्वपूर्ण सूचना
नई दरें

एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार में प्रकाशित विज्ञापनों के लिए डीएवीपी दरें संशोधित करके रु. 190.44 प्रति वर्ग सें.मी. कर दी गई हैं. ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार के 7 दिसंबर, 2013 के अंक से लागू हो गई हैं. सभी विज्ञापनदाताओं से अनुरोध है कि वे इसे नोट कर लें और तदनुसार भुगतान करें.

रोज़गार सारांश

रेलवे

- पश्चिम मध्य रेलवे को 4517 ट्रैकमेन, हैल्पर, खलासी, सफाईवाला आदि की आवश्यकता

अंतिम तिथिः 15.01.2014

- दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रु. 1800 के ग्रेड वेतन में 1206 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित

अंतिम तिथिः 24.01.2014

सं.लो.से.आ.

- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदनपत्र आमंत्रित.

अंतिम तिथिः 02.01.2014

बैंक

- भारतीय स्टेट बैंक को 46 प्रबंधन कार्यपालकों की आवश्यकता.

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथिः 03.01.2014

वेब विशेष

www.rojgarsamachar.gov.in पर वेब विशेष खण्ड के तहत निम्नलिखित आलेख उपलब्ध हैः-

1.रंगभेद विरोध के प्रतीक नेल्सन मंडेला

वित्तीय विश्लेषक के रूप में कॅरिअर

डॉ. शर्मिष्ठा शर्मा

वित्तीय विश्लेषक वह व्यक्ति होता है जो वित्तीय मामलों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करता है. वित्तीय विश्लेषक व्यक्तियों तथा संगठनों को इस तथ्य पर सहायता करता है कि उनकी धन-राशि किस तरह निवेश की जाए. वित्तीय विश्लेषक जब गणितीय मॉडल्स एवं कंप्यूटर समर्थित सिमुलेशन की सहायता से जटिल वित्तीय विश्लेषण करता है तो प्रायः उसे वित्तीय इंजीनियर भी कहा जाता है. वित्तीय विश्लेषक वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के अतिरिक्त, प्रतिभूति विश्लेषण, निवेश-विश्लेषण, इक्विटी विश्लेषण, तकनीकी पोर्टफोलियों विश्लेषण तथा वित्तीय बाजार माहौल का मूल्यांकन भी करता है. वित्तीय विश्लेषक बनने के लिए सशक्त विश्लेषिक कौशल होना अनिवार्य है. इसलिए गणित, सांख्यिकी या परिचालन अनुसंधान का कुछ ज्ञान होना आवश्यक माना जाता है.

योग्यताः

वित्तीय विश्लेषक बनने के लिए वाणिज्य स्नातक (बी.कॉम.), गणित एवं सांख्यिकी वैकल्पिक विषयों के साथ कला स्नातक (बीए-अर्थशास्त्र) होना आवश्यक है. एम.बीए (वित्त), एम.ए. (अर्थशास्त्र), एम.कॉम, सी.ए. जैसी प्रबंधन में अतिरिक्त डिग्रियां वित्तीय विश्लेषक के रूप में रोज़गार की संभावना को और बढ़ाती हैं. वित्तीय विश्लेषक के रूप में शानदार कॅरिअर बनाने के लिए कोई चार्टरित वित्तीय विश्लेषक (सी.एफ.ए) पाठ्यक्रम प्रायः उक्त उल्लिखित सभी योग्यताओं का पूरक होता है.

किसी वित्तीय विश्लेषक का कॅरिअर व्यावहारिक वित्तीय कार्यों की जानकारी होने की मांग करता है. इसलिए शैक्षिक योग्यताओं के साथ-साथ किसी वित्तीय संगठन में इंटर्न के रूप में कार्य करना संबंधित विशेषज्ञता प्राप्त करने में सहायक हो सकता है. एम.एस.एक्सेल, एम.एस.पॉवर प्वाइंट पर फोकस के साथ कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा जैसी कुछ अतिरिक्त योग्यताएं छात्रों को वित्तीय विश्लेषक के रूप में रोज़गार दिलाने में सहायक होती हैं. वित्तीय विश्लेषक को अनेक सूचना हस्तन करनी होती है, जिनकी उसे एक रिपोर्ट के रूप में व्याख्या तथा प्रस्तुति करनी होती है. इसलिए ग्राहकों से निपटने के लिए अंतर-वैयक्तिक कौशल तथा शानदार अभिव्यक्ति कौशल होना अनिवार्य है.

वित्तीय विश्लेषक बनने के लिए, एक पाठ्यक्रम जो छात्रों को बहुत अधिक सहायता करता है वह है एक दो वर्षीय गहन कार्य-एवं-अध्ययन कार्यक्रम सी.सी.ए.पी. (क्रिसिल सर्टिफाइड एनालिस्ट प्रोग्राम), जो शिक्षार्थी को असाधारण वित्तीय एवं विश्लेषिक कौशल दिलाने में पाठ्यक्रम कार्य, कार्य-असाइनमेंट तथा इंटरएक्टिव वर्कशॉप से युक्त होता है. कार्यक्रम का लक्ष्य क्रिसिल में विभिन्न विश्लेषक भूमिकाओं के लिए विश्व श्रेणी के वित्तीय व्यवसायी का विकास करने पर होता है. विवरण **http://crisil.com/ccap/about-ccap-html** पर देख सकते हैं. भारत में वित्तीय विश्लेषकों को शासित करने वाला शीर्षस्थ निकाय-भारतीय निवेश व्यवसायी एसोशिऐशन है. ऐसे अनेक पाठ्यक्रम हैं जो वित्तीय विश्लेषक बनने के लिए ज्ञान का विकास करने के लिए विशेष रूप से

(शेष पृष्ठ 56 पर)

दिल्ली पोस्टल पंजीकरण संख्या डीएल.एसडब्ल्यू 1/4100/2012.14 यू. (सी.).107/2012.14 पूर्व शुल्क के बिना डाक में डालने की अनुमति आर.एन.आई. 28729/76 एन.डी.पी.एस.ओ. नई दिल्ली 14/16.12.2013 (₹ 8) प्रकाशन तिथि : 12.12.2013

न्यूज़ डाइजेस्ट

■ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश को विभाजित कर अलग तेलंगाना राज्य के गठन संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है. देश का 29वां राज्य बनने वाले इस राज्य में 10 जिले होंगे. इस संबंध में विवादास्पद मुद्दों पर विचार के लिए बने मंत्रिसमूह की अधिकतर सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है. अब यह विधेयक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास जाएगा, जिसे वे आंध्र प्रदेश विधानसभा को भेजेंगे. इस विधेयक के मुख्य अंश इस प्रकार हैं : प्रस्तावित तेलंगाना राज्य में 10 जिले और शेष आंध्र प्रदेश में 13 जिले होंगे; अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम क्षेत्र दोनों की संयुक्त राजधानी होगा ; अधिसूचना के **45 दिनों के भीतर** विशेषज्ञ समिति तेलंगाना राज्य के लिए एक नई राजधानी की पहचान करेगी ; दोनों राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा ; दोनों राज्यों को समान अवसर देने के लिए उन्हें संविधान के अनुच्छेद 371-डी के तहत विशेष दर्जा दिया जाएगा. तेलंगाना के राज्यपाल पर संयुक्त राजधानी क्षेत्र के निवासियों के जीवन, आज़ादी और संपत्ति की विशेष जिम्मेदारी होगी ; राज्यपाल की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा दो सलाहकारों की नियुक्ति की जा सकती है. आंध्र प्रदेश की विधान परिषद में 50 और तेलंगाना की विधान परिषद में 40 सीटें होंगी. तेलंगाना से राज्यसभा की 7 और आंध्र प्रदेश से 11 सीटें होंगी. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लोकसभा की क्रमशः 17 और 25 सीटे होंगी. तेलंगाना में विधानसभा की 119 और आंध्र प्रदेश की 175 सीटें होंगी.

■ पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिल्ली में इस विधानसभा चुनावों में 65 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ. चुनाव आयोग के अनुसार युवा मतदाताओं ने काफी भारी मात्रा में मतदान किया. 2008 के विधानसभा चुनावों में 57.8 प्रतिशत, 2003 में 54.42 प्रतिशत, 1998 में 49 प्रतिशत और 1993 में 61.8 प्रतिशत मतदान हुआ था. दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 810 उम्मीदवार मैदान में थे. राजस्थान में भी अब तक का सबसे अधिक 72.9 प्रतिशित रिकॉर्ड मतदान हुआ. राजस्थान में 2003 में औसत 68.2 प्रतिशत मतदान हुआ था. जैसलमेर में लगभग 85 प्रतिशत मतदान हुआ.

■ दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोध के प्रतीक नेल्सन मंडेला का 5 दिसंबर को जोहांसबर्ग में उनके निवास में निधन हो गया. वे 95 वर्ष के थे. 1960 में रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले वे पहले व्यक्तियों में से एक थे. 1994 में बिना किसी रंगभेद के हुए ऐतिहासिक चुनावों में वह राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और 1999 को सेवानिवृत्त हुए. उन्हें 250 से भी ज्यादा सम्मान प्राप्त हुए, जिसमें 1993 में प्राप्त शांति का नोबेल पुरस्कार, यूएस प्रेजिडेंसियल मेडल ऑफ फ्रीडम, सोवियत ऑडर ऑफ लेनिन तथा भारत रत्न शामिल है. **(अधिक जानकारी के लिए वेब विशेष देखें)**

■ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो का मंगलयान भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई अब तक की सबसे दूर वस्तु बन गया है. दूसरे ग्रह पर भेजा जाने वाला भारत का पहला मिशन मंगलयान पृथ्वी के गुरुत्वाकार्षण से बाहर निकल गया है तथा उसने चंद्रमा की कक्षा को पार कर लिया है. अगले साल सितंबर में मंगल ग्रह के करीब पहुंचने से पहले मंगलयान को 680 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करनी है. सफलतापूर्वक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ने में गति देने के लिए इसरो ने अंतरिक्षयान में लगे प्रोपल्शन प्रणाली को 23 मिनट के लंबे समय तक चालू रखा. अंतरिक्ष की शब्दावली में इसे ट्रांस मार्स इंजेक्शन कहा जाता है (टीएमआई).

■ सेना के सामरिक बल कमान (स्ट्रेटिजिक फोर्स कमांड, एसएफसी) ने ओड़िशा के बालासोर के निकट इंटिग्रेटिड टेस्ट रेंज से सतह से सतह तक मार करने वाली पृथ्वी द्वितीय मिसाइल का सफल परीक्षण किया. 250-350 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल 350 किलोग्राम का परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है. एसएफसी परमाणु हथियारों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है.

■ जापान के सम्राट अकिहितो और साम्राज्ञी मिचिको 6 दिन की यात्रा पर भारत आए जिस पर सरकार ने कहा ''यह इस साल भारत के राजनयिक संबंधों के सबसे बेहतरीन पलों में से एक है''. यह पहली बार है कि जापान के सम्राट और साम्राज्ञी भारत आए हैं. यह भी पहली बार हुआ है कि 50 साल के अंतराल के बाद राजकीय यात्रा पर आए इन दो गणमान्य व्यक्तियों की भारत ने फिर से मेज़बानी की है.

■ 44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) सम्पन्न हो गया है. समारोह के समापन समारोह में पूर्वी तिमोर में उपनिवेशवाद के बाद बनी पहली फीचर फिल्म 'बीटरिज़स वॉर' को 2013 हेतु सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण मयूर पुरस्कार तथा 40 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया. इस फिल्म के सह-निर्देशक बैटी राइस की निर्देशक के रूप में यह पहली फिल्म है. बांग्ला फिल्म 'आपुर पांचाली' के निर्देशक कौशिक गांगुली को रजत मयूर तथा 15 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया. यह फिल्म सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि है.

■ कपूरथला के गगनजीत भुल्लर इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. भुल्लर ने थाईलैंड के जैज़ जेनवॉटननोंड से हर दौर में बढ़त बनाई, केवल तीसरे दौर का मुकाबला बराबर का रहा.

■ भारत की पी वी सिंधू ने कनाडा की मिशैल ली को हराकर मकाऊ ओपन ग्रां प्रीं गोल्ड का खिताब जीत लिया है. मई में मलेशिया ओपन अपने नाम करने के बाद यह उनकी दूसरी खिताबी जीत है. 18 वर्षीय सिंधू ने ली को 37 मिनट में 21-15, 21-12 से हराया. इनाम के रूप में उन्हें 9,000 डॉलर की राशि प्रदान की गई.

वित्तीय विश्लेषक का ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

तैयार किए गए हैं. कुछ प्रसिद्ध वैश्विक तथा भारतीय पाठ्यक्रम निम्नानुसार हैं:-

विश्व-पाठ्यक्रम :

◆ लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस (एल.एस.बी.एफ.) से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम. यह कार्यक्रम निवेश प्रबंधन के क्षेत्र में एक व्यापक प्रस्तुति है. यह पाठ्यक्रम एक 4-6 सप्ताह फार्मेट में व्यापक पद्धत्ति से दिया जाता है.

◆ ईस्टर्न मिशीगन यूनिवर्सिटी-कॉलेज ऑफ बिजनेस से वित्त में स्नातक प्रमाणपत्र. इस कार्यक्रम में प्रवेश केवल उन छात्रों को दिया जाता है जो किसी मान्यताप्राप्त संस्था से 4.0 (+) पर न्यूनतम 2.7 जीपीए के साथ कोई स्नातक डिग्रीधारी होते हैं.

◆ मास्टर ऑफ साइंस इन फाइनेंस एनालिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सेन फ्रांसिस्को एक पाठ्यक्रम चलाता है जो नए स्नातकों एवं छात्रों को उनके कॅरिअर के प्रारंभिक चरणों में देने के लिए बनाया गया है. एमएसएफए एक 18 महीनों का कार्यक्रम है जिसमें अनुसंधान प्रैकिटकम या शैक्षिक इमर्जन शामिल है.

◆ मास्टर ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ बिजनेस (यू. एन.एस.डब्ल्यू.) यह पाठ्यक्रम विश्लेषिक कौशल के साथ लेखाकरण एवं वित्त में व्यापक ज्ञान देता है.

◆ मास्टर्स इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनालिसिस यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो-यह 12 महीने का एक पूर्णकालिक एम.एससी. कार्यक्रम है, जिसमें सी.एफ.ए. लेवल-1 पाठ्यक्रम के भाग शामिल होते हैं.

भारतीय पाठ्यक्रम :

◆ वित्तीय एवं निवेश विश्लेषण में स्नातक (बी.एफ-आई.ए.) व्यवसाय अध्ययन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय. यह एक पूर्णकालिक स्नातक कार्यक्रम है जो वित्तीय विश्लेषण में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है.

◆ भारतीय वित्तीय नियोजन संस्थान, नई दिल्ली. यह संस्थान वित्तीय नियोजन एवं संपदा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, प्रमाणित वित्तीय नियोजक एवं सी.एम. तथा सी.एफ.ए. में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाता है.

◆ ग्लोबल एम.बी.ए. प्रोग्राम फाइनेंस मैनेजमेंट, एस.पी.जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनजमेंट. वैश्विक एम.बी.ए. कार्यक्रम में वित्तीय विशेषज्ञता वित्तीय सेवा एवं प्रतिभूतियों से संबंधित मामलों में दक्षता प्रदान करती है, जिसमें बड़ी प्रौद्योगिकी फर्मों, बड़े निगमों तथा उद्यम कंपनियों के बारे में संबंधित जानकारी भी शामिल है.

◆ बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र कार्यक्रम (पी.जी.पी.बी.एफ.एस.), जेवियर प्रबंधन संस्थान, भुवनेश्वर. इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को वित्तीय सेवा व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों के मूल्यांकन से संबंधित संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों का ज्ञान दिया जाएगा.

◆ एम.एससी.टेक. फाइनेंस, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (बी.आई.टी.एस., पिलानी). यह एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम है जो छात्रों को विश्लेषिक वित्त के बारे में अध्ययन करने में सक्षम बनाता है. इस पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु में कम्प्यूटिंग के ज्ञान के साथ वित्तीय इंजीनियरी के घटक शामिल हैं.

कार्य-प्रोफाइल :

बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र, प्रतिभूति फर्मों तथा म्युचुअल फंड कंपनियों में रोज़गार के अनेक अवसर हैं. जो विभिन्न प्रोफाइल उपलब्ध हैं उनमें कनिष्ठ वित्तीय विश्लेषक, वित्तीय विश्लेषक, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी, अनुसंधान विश्लेषक-विकल्प नीतियां आदि शामिल है.

वेतन :

वित्तीय विश्लेषक का वेतन मुख्य रूप से उसके कौशल पर निर्भर होता है. वर्षों के निरंतर अनुभव के बाद वेतन-संरचना में पर्याप्त वृद्धि होती हैं.

संभावना :

भारत में वित्तीय क्षेत्र 8.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है. उदारीकरण अवधि के पश्चात् वित्तीय रोज़गार में महत्त्वपूर्ण विकास देखा गया है. भारतीय बैंकिंग उद्योग रु. 77 ट्रिलियन (1.25 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर) का है और इसलिए वित्तीय विश्लेषकों के रोज़गार की असीम संभावना है. इसी तरह, बीमा क्षेत्र के, प्रतिभूति एवं म्युचअल फंड सहित अगले 15-20 वर्षों में 15-20 प्रतिशत की कंपाउंडेड औसत विकास दर पर आगे बढ़ने की प्रत्याशा है. यह वित्तीय विश्लेषकों के लिए रोज़गार का आश्वासन देता है.

(लेखिका डिपार्टमेंट ऑफ़ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्नोवेशन इन टैक्नोलोजी एंड मैनेजमेंट, नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हैं.

ई-मेल:- chiefeditor@cpmr.org.in)

भारत सरकार

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय
नॉनग्रिम हिल्स, शिलांग-793003
विज्ञापन सं. एनईसी/एडीएम/50/80
वॉल्यू VI

पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय को (1) **प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि अनुबंध सहित)**/आमेलन पर **कार्यकारी अभियंता (सिविल)** और (2) **प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि अनुबंध सहित)** पर अधिशासी अभियंता (विद्युत) के पदों को वेतनमान रु. 10000-325-15200/-(असंशोधित) (संशोधित) पीबी-3, रु. 15600-39100/-. जीपी रु. 6600/- में भरने हेतु सुयोग्य अधिकारियों की तलाश है. पद के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को **56 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए. वेतन एवं प्रतिनियुक्ति की अन्य शर्तें एवं निबंधन समय-समय पर यथा संशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 6/8/2009-स्था.(वेतन-2)दिनांक 17.06.2010 के अनुरूप विनियमित होंगी. संवर्ग प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे ऐसे पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र, जिनकी सेवायें तत्काल प्रतिनियुक्ति आधार पर मुक्त की जा सकती हैं, इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से **60 दिनों के भीतर निदेशक (प्रशासन)** के पास अग्रेषित करें. पात्रता मानदंड, कार्य अपेक्षा, अर्हताएं और अनुभव, आवेदन प्रपत्र और अन्य विवरण के लिए एनईसी वेबसाइट: **http://necouncil.gov.in.** देखें.

(डेविड ललमलसामा)
निदेशक (प्रशा.)
रो.स. 37/34

उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण

- **ब्याज दर 4 प्रतिशत वार्षिक**
- **भारत में अध्यन हेतु 10 लाख रुपये तक**
- **विदेश में अध्यन हेतु 20 लाख रुपये तक**
- **वेबसाइट www.nhfdc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करें**

नि:शक्तजनों का सशक्तिकरण

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेन्स एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन
(नि:शक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
रेड क्रॉस भवन, सैक्टर-12, फरीदाबाद-121007
दूरभाष : 0129-2287512, 0129-2287513, फैक्स : 0129-2284371
ई-मेल : nhfdc97@gmail.com, वेबसाइट : www.nhfdc.nic.in रो.स. 37/13

रोज़गार समाचार

निधि पांडे
निदेशक, महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक
डॉ. ममता रानी
संपादक
नलिनी रानी
संपादक (विज्ञापन एवं संपादकीय)
इरशाद अली (संपादक वितरण)
आफ़ाक़ अहमद एहसानी
संपादक
विनोद कुमार मीणा
संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
पी.के. मंडल
वरिष्ठ कलाकार
केपी मणिलाल
लेखा अधिकारी

संपादकीय कार्यालय
रोज़गार समाचार
पूर्वी खण्ड IV तल-5, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली-110066

ई-मेल-संपादकीय : enewsedit@gmail.com
विज्ञापन : enewsadvt@yahoo.com

संपादकीय :	: 26163055
विज्ञापन	: 26104284
टेलीफैक्स	: 26193012
वितरण	: 26107405
टैलीफैक्स	: 26175516
प्रोडक्शन	: 26177529
लेखा (विज्ञापन)	: 26193179
लेखा (वितरण)	: 26182079

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए **ईरा जोशी,** अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटिंग प्रेस अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, सी.21 व 22, सेक्टर.59, नोएडा.201301 में मुद्रित, रोज़गार समाचार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ईस्ट ब्लाक.IV, लेवल.5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली.110066 द्वारा प्रकाशित, संपादकः डॉ. ममता रानी